वनों के संरक्षण और सुरक्षा तथा पारिस्थितिक और पर्यावरणीय स्थिरता की जरूरत के कारण वनों पर आधारित उद्योगों को कच्चे माल की उपलब्धता पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में कहा गया है कि वनों पर अधारित उद्योगों को अपने कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने के लिए जहां तक सम्भव हो, अधिमानतः फैक्टरी और कच्चा माल पैदा करने में सक्षम व्यक्तियों के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित करके कच्चा माल पैदा करना चाहिए।

(ग) उद्योगों को वृक्ष लगाने के लिए वन भूमि पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय को वित्तीय सहायता

2361. **श्री अजीत जोगी :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को दी जा रही वित्तीय सहायता दूसरे राज्यों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की तुलना में कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं तथा इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमनभाई मेहता) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के संस्थागत अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए विकास अनुदान प्रदान करता है जैसे भवन, पुस्तक और पत्रिकायें, उपस्कर और अन्य सुविधायें जो अध्यापन और अनुसंधान की कोटि और स्तर को प्रोन्नत करने के लिए तैयार की गई हैं। आयोग विशेष सहायता की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत भी अनुदान प्रदान करता है। विश्वविद्यालयों और कालेजों को इस बात पर ध्यान दिये बिना कि ये किन राज्यों से संबंधित हैं इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार अनुदान दिये जाते हैं। सहायता की राशि छात्रों के नामांकन अध्यापकों और अध्यापन विभागों की संख्या और इसके विकास के स्तर पर निर्भर करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों और कालेजों की तुलना में मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान देने में, कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है।

मध्य प्रदेश में योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई रेल परियोजनाएं

2362. **श्री अजीत जोगी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1989-90 में मध्य प्रदेश में रेलवे से संबंधित किसी परियोजना को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस अवधि के दौरान किसी अन्य राज्य के रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) रेलवे परियोजनाओं का अनुमोदन राज्यवार नहीं करके अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। वर्ष 1989-90 के दौरान योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित रेलवे परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था :